बाजार में औद्योगिक सब्सिडी का बढ़ता असर

भारत के लिए चुनौती : समान प्रतिस्पर्धा नहीं, नीति संतुलन जरूरी

नई दिल्ली, 17 जून. औद्योगिकी रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों के पेरिस स्थित मंच- ऑर्गनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) की जून,2026 की मैजिक डेटाबेस रिपोर्ट में इस तथ्य को उभारा गया कि औद्योगिक सब्सिडी अब वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा बन चुकी है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जब सरकारों द्वारा दी जाने वाली ऐसी सब्सिडी बड़ी हों, निरंतर दी जा रही हों और लक्ष्य कर के दी जा रही हों, तो वे बाजारों को महत्वपूर्ण रूप से विकृत कर सकती हैं. रिपोर्ट के आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 2005 से 2024 के बीच भारतीय और कुछ अन्य देशों की कंपनियों को चीन की कंपनियों की तुलना में काफी कम सरकारी सहायता प्राप्त हुई. ओईसीडी की औद्योगिक सब्सिडी रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की सब्सिडी किसी देश के नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं लेकिन उनकी संरचना और लक्ष्यीकरण के आधार पर वे व्यापार और प्रतिस्पर्धा को भी विकृत करती हैं. इस संदर्भ में भारत (या भारत जैसे किसी देश) के लिए वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि चीन के सब्सिडी मॉडल को बाहर से कैसे बदला जाए, बल्कि यह है कि भारत बिना अत्यधिक रक्षात्मक या प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाए, अपनी कंपनियों की रक्षा कैसे करे, नीतिगत स्वतंत्रता कैसे बनाए रखे और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को कैसे मजबूत करे? इसका उत्तर व्यापारिक उपायों, घरेलू क्षमताओं के निर्माण, अधिक बुद्धिमान औद्योगिक नीति और मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के संयोजन में निहित है.

> भारत के लिए इसका मुख्य निहितार्थ यह है कि चीन के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा हमेशा बराबरी का मुकाबला नहीं होती. यदि विदेशी प्रतिस्पर्धियों को अधिक अनुदान, कर रियायतें या बाजार दर से कम लागत पर कर्ज सहायता मिलती है, तो भारतीय कंपनियों को ऐसी लागत व्यवस्था से मुकाबला करना पड़ सकता है जिसकी भरपाई केवल निजी प्रयासों से करना कठिन हो.

भारी उतार-चढ़ाव के बाद रुपया दो पैसे की गिरावट

मुंबई, 17 जून. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में मंगलवार को रुपये में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया और अंत में यह दो पैसे टूटकर 94.60 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ. दोपहर बाद एक समय रुपया अचानक 102 पैसे की मजबूती के साथ 93.56 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच गया था. लेकिन जिस तेजी के साथ यह ऊपर गया था उसी तेजी से 94.52 रुपये प्रति डॉलर तक गिर गया. यह भारी उतार-चढ़ाव आधे घंटे के भीतर देखने को मिला. कच्चे तेल में नरमी और शेयर बाजारों में तेजी से रुपये को समर्थन मिला, लेकिन कम भाव पर डॉलर की लिवाली आने से बाद में भारतीय मुद्रा दबाव में आ गयी. यह 11 पैसे टूटकर 94.69 रुपये प्रति डॉलर पर खुली थी. इसका दिन का उच्चतम स्तर 93.56 रुपये और निचला स्तर 94.72 रुपये प्रति डॉलर रहा.

टीसीएस को वैश्विक आईटी बनाने का ठेका

टीसीएस इलोपैक की रणनीतिक आईटी भागीदार बनेगी

इलोपैक का कारोबार 40 से अधिक देशों में फैला

मुंबई, 17 जून. प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को कागज के पैकेजिंग उत्पाद और फिलिंग उपकरण बनाने वाली कंपनी इलोपैक से उसके आईटी संचालन में आमूलचूल बदलाव के लिए एक बहुवर्षीय ठेका मिला है.

इलोपैक का कारोबार 40 से अधिक देशों में फैला हुआ है और वह 70 से अधिक बाजारों में सेवाएं प्रदान करती है. इस साझेदारी के तहत टीसीएस इलोपैक की रणनीतिक आईटी भागीदार बनेगी.

वह प्रक्रिया-केंद्रित परिचालन मॉडल के माध्यम से उसके वैश्विक आईटी संचालन के रूपांतरण और प्रबंधन की जिम्मेदारी उठायेगी. टीसीएस ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि वह इलोपैक के आईटी संचालन में उन्नत विश्लेषण और स्वचालन का समावेश करेगी.

इसमें भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाले एआई-संचालित भविष्योन्मुख सेवा वितरण समाधान सूट कोग्निक्स की तैनाती भी शामिल है. इसमें एक एकीकृत सेवा डेस्क की स्थापना और प्रमुख एंटरप्राइज एप्लिकेशन का उन्नयन भी किया जायेगा.

> इससे उसकी दक्षता बढ़ाने, उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने और अपने विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी. टीसीएस के विनिर्माण व्यवसाय के अध्यक्ष अनुपम सिंघल ने कहा कि आज के कारोबारी वातावरण में उद्यमों को ऐसे डिजिटल आधार की आवश्यकता है जो लगातार जरूरत के अनुसार अनुकूलित और विकसित हो सकें. इस साझेदारी के माध्यम से कंपनी इलोपैक को एआई, स्वचालन और क्लाउड की मदद से उसके आईटी संचालन का आधुनिकीकरण करने में सहायता करेगी.

कच्चे तेल के आयात के लिए सिर्फ छह देशों पर जोखिम

अपनी जरूरत का 88 प्रतिशत कच्चा तेल,

48 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और 26 प्रतिशत

नई दिल्ली, 17 जून (वार्ता) काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) ने चेतावनी दी है कि कच्चे तेल के आयात में सिर्फ छह देशों पर भारत की अत्यधिक निर्भरता देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

सीईईडब्ल्यू की बुधवार को जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कच्चे तेल का 85 प्रतिशत से अधिक आयात केवल छह देशों से करता है, जिनमें रूस और पांच पश्चिम एशियाई देश शामिल हैं. यह आपूर्ति में कोई रुकावट आने पर, जैसा की इस समय परिस्थिति बनी है, लचीलेपन को सीमित कर रहा है. इसमें बताया गया है कि सिर्फ आयात पर निर्भरता ही नहीं, रिफाइनरियों की बनावट के कारण भी जोखिम है, क्योंकि देश केवल कुछ विशेष श्रेणी के कच्चे तेल का ही कम खर्च में शोधन करने की क्षमता रखता है.

अहमदाबाद मंडल ने ओएचई की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक

अहमदाबाद, 17 जून. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) की जांच के लिए ड्रोन से हवाई निरीक्षण का सफल परीक्षण किया है. यह भारतीय रेल में नई तकनीक के जरिए सुरक्षित रखरखाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

रेलवे बोर्ड द्वारा अप्रैल 2026 में आरडीएसओ के निर्देश संख्या मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम रेलवे इस तकनीक का उपयोग शुरू करने वाले प्रमुख जोनों में शामिल हो गया है. 8 जून 2026 को किए गए इस परीक्षण से पारंपरिक मैनुअल जांच की जगह आधुनिक और सुरक्षित व्यवस्था की ओर बढ़ने का रास्ता खुला है.

ड्रोन से ओएचई का हवाई निरीक्षण- डीजीसीए के मानकों के अनुसार हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों और जियो-टैगिंग सुविधा वाले ड्रोन की मदद से अहमदाबाद मंडल की टीम ने मास्ट संख्या 493-494 के बीच ओएचई संरचनाओं का निरीक्षण किया. जांच के दौरान मिली हर खराबी की तस्वीर ली गई, उसे जीपीएस लोकेशन के साथ दर्ज किया गया और उसकी गंभीरता का आकलन किया गया. इससे जरूरी मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा. यह निरीक्षण आरडीएसओ द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश (ऋड्ढ/ढ्ढ्/0060) के अनुसार किया गया. इन दिशा-निर्देशों में डीजीसीए से मान्यता प्राप्त ड्रोन, जीपीएस/जीएनएसएस, जियो-टैग्ड तस्वीरें और थर्मल स्कैनिंग जैसी सुविधाओं का प्रावधान है.

> **समय रहते मिली कई गंभीर खराबियां**
>
> परीक्षण के दौरान कई तरह की खराबियां सामने आईं. इनमें इंसुलेटरों पर फ्लैश मार्क, कैंटिलीवर पर लटकी बाहरी सामग्री, पोर्टल संरचनाओं और कैंटिलीवर पर बने पक्षियों के घोंसले तथा वहां बैठे पक्षी शामिल थे. इसके अलावा कैटेनरी स्ट्रैंड में नुकसान जैसी गंभीर खराबियां भी मिलीं, जिन्हें सामान्य जांच के दौरान पहचानना मुश्किल होता है. ड्रोन से ली गई साफ और जियो-टैग्ड तस्वीरों की मदद से इन खराबियों का सही स्थान पता चला. इससे समय पर मरम्मत कर भविष्य में ओएचई ट्रिपिंग, बिजली आपूर्ति में रुकावट और अन्य परिचालन समस्याओं को रोका जा सकेगा.

शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स फिर 77 हजार अंक के पार

मुंबई, 17 जून. अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद से शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार चौथे दिन तेजी बनी रही और बीएसई का सेंसेक्स 77 हजार अंक के पार पहुंचने में सफल रहा.

सुबह बढ़त में खुलने के बाद सेंसेक्स 347.14 अंक (0.45 प्रतिशत) चढ़कर 77,155.62 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 96.55 अंक यानी 0.40 प्रतिशत ऊपर 24,085.70 अंक रहा. यह दोनों का 08 मई के बाद का उच्चतम स्तर है. अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर से पहले निवेशक बाजार में लिवाल बने हुए हैं. वृहत बाजार में भी तेजी है. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.30 प्रतिशत और स्मॉलकैप 100 सूचकांक 0.79 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. आईटी, धातु, सार्वजनिक बैंकों और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों के सूचकांक मजबूत रहे. वहीं, ऑटो और रियल्टी समूहों में गिरावट देखी गयी. सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेंट में सात प्रतिशत का जबरदस्त उछाल देखा गया. बीईएल का शेयर भी तीन फीसदी चढ़ा.

रिलायंस का एजीएम डिजिटल देगा ई-वोटिंग

डिविडेंड और टैक्सेशन से जुड़ी जानकारियां

मुंबई, 17 जून. मुंबई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपनी 49वीं वार्षिक आम बैठक से पहले शेयरधारकों के लिए व्हाट्सप्प आधारित एजीएमडिजिटल असिस्टेंट सक्रिय कर दिया है. कंपनी की यह सुविधा लगातार छठे वर्ष उपलब्ध कराई जा रही है.

इसके जरिए 44 लाख से अधिक शेयरधारक एजीएम से जुड़ी जानकारी, दस्तावेज़, मतदान प्रक्रिया और सहायता सेवाओं तक सीधे अपने मोबाइल फोन से पहुंच सकेंगे. कंपनी ने एजीएम डिजिटल असिस्टेंट को व्हाट्सप्प नंबर +91 79771 11111 पर सक्रिय कर दिया है. शेयरधारकों को केवल इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर व्हाट्सप्प पर संदेश भेजना होगा। इसके बाद चैटबॉट का मेन्यू खुल जाएगा, जहां से वे एजीएम से संबंधित विभिन्न सेवाओं और सूचनाओं का लाभ उठा सकेंगे.

> रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 49वीं वार्षिक आम बैठक 19 जून 2026, शुक्रवार को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिओ इवेंट प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी. रिलायंस ने वर्ष 2020 में एजीएम से जुड़े प्रश्नों और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के उद्देश्य से यह डिजिटल पहल शुरू की थी. कंपनी का दावा है कि एजीएम के लिए समर्पित व्हाट्सप्प चैटबॉट सेवा शुरू करने वाली वह भारत की पहली कंपनी है.

एचडीएफसी बैंक ने बॉन्ड जारी कर जुटाये 75 करोड़ डॉलर

मुंबई, 17 जून. निजी क्षेत्र के अग्रणी एचडीएफसी बैंक ने वरीय असुरक्षित बॉन्ड जारी कर 75 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटायी है. बैंक ने मंगलवार देर रात शेयर बाजार को बताया कि डॉलर में ये बॉन्ड गिफ्ट-सिटी स्थित इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और एनएसई आईएफएससी के जरिये जारी 16 जून को जारी किये गये. इन्हें मूडीज से बीएए3 और एसएंडपी से बीबीबी रेटिंग मिलने की उम्मीद है. इस राशि का इस्तेमाल बैंक अपनै मुख्य कारोबार के विस्तार के लिए करेगा.

हिमालय तनिष्क अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का गठन

गाजियाबाद, 17 जून. हिमालय तनिष्क अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन% का गठन गाज़ियाबाद के लेबर कमिश्नर की देखरेख में हुए लोकतांत्रिक चुनावों के बाद किया गया है.

10 सदस्यों वाला यह नया बोर्ड निवासियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा, सुविधाओं के रखरखाव का प्रबंधन करेगा और कम्युनिटी वेलफेयर (सामुदायिक कल्याण) का काम देखेगा. हिमालय तनिष्क अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने आधिकारिक चुनावों के बाद नए गवर्निंग बोर्ड की घोषणा की

गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश — राज नगर एक्सटेंशन में स्थित एक प्रमुख रेजिडेंशियल सोसाइटी, %हिमालय तनिष्क% के निवासी नई %हिमालय तनिष्क अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन% के आधिकारिक गठन और शपथ ग्रहण की घोषणा करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं. यह गवर्निंग बोर्ड गाज़ियाबाद के लेबर कमिश्नर की देखरेख में बहुत सावधानी से आयोजित पारदर्शी और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के बाद बनाया गया है. यह उपलब्धि निवासियों के लिए एक बड़ा कदम है, जो उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के तहत एकजुट प्रतिनिधित्व, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस (ढांचे का रखरखाव) और सोसाइटी के कामकाज के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करती है.

नवनिर्वाचित लीडरशिप कमेटी के पास काफी अनुभव है और वे रहने के अनुभव को बेहतर बनाने, सामुदायिक सुविधाओं को सुरक्षित करने और एक जीवंत पड़ोस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

राज्यसभा चुनाव को लेकर क्लाइमेक्स पर पहुंची राजनीति

रांची. राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधि तेज है. दो सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव की रणनीति अब होटल में शिफ्ट हो गई है. राजधानी के एक होटल में एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के समर्थन में विधायक जमे हुए हैं, जबकि दूसरी ओर स्टेशन रोड स्थित एक होटल के कमरा नंबर 108 में कांग्रेस के विधायक एवं मंत्री अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए जमे हुए हैं.

राजद विधायकों से मिले कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा- इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी के. राजू के अलावा कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद थे. इससे पहले राजद विधायकों से कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के साथ कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की. इस मौके पर राजद के भोला यादव भी मौजूद रहे. राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के 5-6 विधायक संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी को नई-नई चाल चलने में महारथ हासिल है बावजूद इसके हम लोग पूरी तरह जीत के लिए आश्वस्त हैं. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है. महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत के साथ हम लोग पश्चिम बंगाल और बिहार में बीजेपी की जीत के बाद झारखंड में उसके मंसूबों पर पानी फेरने का काम करेंगे.

बस में बैठकर मतदान करने निकलेंगे एनडीए विधायक- राजधानी के एक आलिशान होटल में जमे हुए एनडीए विधायकों ने भी जीत का दावा करते हुए कहा कि विधायक अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करेंगे. निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत सुनिश्चित करने पहुंचे इन विधायकों के लिए 18 जून तक इस होटल का कमरा बुक किया गया है.

> **2 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को मतदान**
>
> गौरतलब है कि 18 जून की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान होंगे. राज्यसभा की दो सीटों के लिए जेएमएम के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनाव मैदान में हैं. मतदान झारखंड विधानसभा में होगा. मतदान के बाद वोटों की गिनती उसी दिन यानी 18 जून की शाम 5 बजे से शुरू होगी और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे. इस चुनाव में झारखंड विधानसभा के सभी 81 विधायक मतदान करेंगे.

उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद बदलेंगे पाला!

आनन-फानन में संजय राउत भी पहुंचे दिल्ली

मुंबई. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगे राजनीतिक झटके की चर्चाओं के बीच अब महाराष्ट्र से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए चिंता बढ़ा सकती हैं.

एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद बगावत की तैयारी में हैं. यदि यह घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. जानकारी के अनुसार, दो सांसद पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं. शिरडी से सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे और यवतमाल से सांसद संजय देशमुख फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं. खबरों के मुताबिक, ये सात सांसद पहले अलग समूह का गठन कर सकते हैं और उसके बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. बगावत की चर्चाओं में जिन सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें संजय जाधव, संजय पाटिल, नागेश बापूराव अष्टिकर, ओमप्रकाश राजे निंबालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय देशमुख शामिल हैं. दूसरी ओर, पार्टी में संभावित टूट को रोकने के प्रयासों के तहत अनिल देसाई और संजय राउत दिल्ली में डटे हुए हैं.

> **'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर बढ़ी अटकलें**
>
> महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर चर्चाएं तेज हैं. माना जा रहा था कि इस अभियान के तहत कुछ सांसद शिवसेना (शिंदे गुट) का दामन थाम सकते हैं. हालांकि, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐसे दावों को खारिज किया है. शिंदे का कहना था कि चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब किसी प्रकार के 'नंबर गेम' की आवश्यकता नहीं है.

झारखंड में सहयोगी कांग्रेस के साथ नहीं

रांची. ऐसा लग रहा है कि झारखंड में सहयोगी पार्टियों ने कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़ दिया है. हालांकि इस बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का अनौपचारिक बातचीत में यही कहना है कि शुरुआत कांग्रेस ने की थी. कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए बिना बात किए एकतरफा तरीके से उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी.

जेएमएम के नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस की ओर से हेमंत सोरेन से बात की जाती और तब प्रणब झा के नाम की घोषणा होती तो उसका श्रेय हेमंत सोरेन को जाता है और फिर उनके नेतृत्व में ही राज्यसभा का चुनाव लड़ा जाता. हालांकि एक बार कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित हो गया तो हेमंत सोरेन उनके साथ नामांकन कराने गए. हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सहित जेएमएम के दूसरे नेता गुजरात के कारोबारी परिमल नाथवानी को राज्यसभा चुनाव में समर्थन करने के लिए भाजपा पर हमला भी कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वे कांग्रेस की मदद में पूरी तरह से खड़े हैं.

इसका संकेत पिछले दिनों मिला, जब कांग्रेस ने परिमल नाथवानी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई. कांग्रेस ने उनके नामांकन पत्र में तीन कमियां बताईं. इन्हें देखने के बाद चुनाव अधिकारी ने नामांकन होल्ड पर रख दिया. सोचें, इससे कम गड़बड़ी में मध्य प्रदेश में चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया. लेकिन झारखंड में चुनाव अधिकारी ने जो विधानसभा के सचिव हैं, उन्होंने नामांकन होल्ड किया और अगले दिन उसे मंजूर कर लिया. यहां तक कहा जा रहा है कि नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरा नामांकन लिया गया. कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया तो किसी सहयोगी पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया. उलटे कांग्रेस के विधायक और दूसरे नेता विधानसभा में प्रदर्शन करने गए तो पुलिस ने उन्हें रोका और परेशान किया, जिसकी शिकायत उन्होंने की.

एआईएडीएमके में बागियों पर गिरेगी गाज!

चेन्नई. तमिलनाडु में टीवीके का समर्थन करने के बाद एआईएडीएमके ने सख्त रूप अपना लिया है. पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संकेत दिए है कि एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी बागी विधायकों और नेताओं को संगठनात्मक पदों पर बहाल करने के पक्ष में नहीं हैं. खासकर वे पद जो उन्होंने विधानसभा विश्वास मत के दौरान सत्तारूढ़ टीवीके सरकार का समर्थन करने के बाद खो दिए थे.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और पार्टी के अलग-अलग स्तरों पर नेताओं के बागी होने के बाद एआईएडीएमके फिर से एक होने की कोशिश कर रही है. के. पलानीस्वामी भी संगठन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने और विरोध को उभरने से रोकने की कोशिशों में जुटे हुए हैं. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों कि माने तो चुनावी हार और विधानसभा में पार्टी के तीसरे स्थान पर खिसकने के कारण कई नेताओं और कार्यकर्ता परेशानी में पड़ गए है. नेताओं को अब अपने राजनीतिक करियर को लेकर सोच-विचार करना पड़ रहा है. इन चुनौतियों के बावजूद पलानीस्वामी ने आत्मविश्वास दिखाया है और संगठन के भीतर अपना अधिकार मजबूत करने की कोशिश की है.

हाल के हफ्तों में एआईएडीएमके प्रमुख ने बागी गुट से जुड़े कई नेताओं के साथ सुलह करने के लिए कदम उठाए हैं. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत छीने गए संगठनात्मक पदों को वापस देने के मामले में एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा तय कर दी है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि ऐसे नेताओं को फिर से पद देने से पार्टी का आंतरिक अनुशासन बिगड़ सकता है और पार्टी के भीतर सत्ता के कई केंद्र बन सकते हैं.

> **इन बातों का खास ध्यान रख रहे पलानीस्वामी**
>
> पार्टी सूत्रों के अनुसार, पलानीस्वामी इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि ऐसे कदम से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश जाएगा. जिन पदाधिकारियों ने खुलकर पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी थी, उन्हें फिर से पद देने को अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने के तौर पर देखा जा सकता है और इससे महासचिव का अधिकार कमजोर हो सकता है. फिलहाल, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ऐसे संकेत कम ही हैं कि हटाए गए नेताओं को उनकी पुरानी संगठनात्मक भूमिकाएं वापस मिलेंगी. पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि को मुख्यालय सचिव के पद से हटा दिया गया था, जबकि सी.वी. शनमुगम से आयोजन सचिव और विल्लुपुरम ज़िला सचिव के पद छीन लिए गए थे.